



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2009/आश्विन 7, 1931

No. 560]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2009/ASVINA 7, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2009

सं. 112/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 710(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों को भारत में आयात करने पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के तहत लगने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से और कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की क्रमशः धारा 3, 8ख तथा 9क के अंतर्गत इस अधिसूचना के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट सीमा तक छोड़कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनपर उद्ग्रह्य लगने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क, रक्षोपाय शुल्क तथा प्रतिपाटन शुल्क से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

(i) यह कि आयातक को मानद निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.3(iii) के निबंधनों के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कथित सामग्रियों के आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार दिया गया है (जिसे इसके बाद कथित प्राधिकार कहा गया है);

(ii) यह कि कथित प्राधिकार को डेबिट के लिए क्लीयरेंस के समय उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए;

(iii) कथित प्राधिकार में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने के लिए पृष्ठांकन हो,-

(क) कथित प्राधिकार के तहत आयात के लिए अनुमत सामग्री का विवरण, मात्रा एवं मूल्य; और

(ख) आयातित सामग्री से या द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले अंतिम उत्पाद का विवरण और मात्रा;

(iv) कि यदि आयात, निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह पूरा किये जाने के पहले किया जाता है तो आयातित सामग्री के लिए अनापत्ति लेते समय आयातकर्ता उस जमानती या प्रत्याभूति का बंधपत्र उस रूप में तथा उस राशि का भरेगा जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करें जिसके द्वारा वह लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, अपने को इस बात से वचनबद्ध करेगा कि वह उस आयातित सामग्री पर लगाये जाने वाले शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान कहे जाने पर कर देगा जिसके बारे में इस अधिसूचना में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, साथ ही साथ उक्त सामग्री की स्वीकृति की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा।

(v) कि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह पूरा किये जाने के पश्चात यदि आयात किया जाता है तो उस स्थिति में यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के उपनियम(2) अथवा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के तहत सेनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया जा चुका है, तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के लिए स्वीकृति लेते समय उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय का बंध पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित विनिर्माता के कारखाने की शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में किया जायेगा और वह उक्त सामग्री की स्वीकृति मिलने की तारीख से 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है।

आगे शर्त यह है कि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर लगने योग्य अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन उसमें निहित छूट के लिए, तो आयातित सामग्री को इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी स्वीकृति को दिया जा सकता है और इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी पर वह सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का लाभ पाने का पात्र होगा।

(vi) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता है तो, और यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 और नियम 19 के अंतर्गत दी गई सुविधा और सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनवेट का लाभ नहीं लिया है तो और

आयातकर्ता उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को इस बात का प्रमाण भी सौंप देता है तो आयातित सामग्री को शर्त (v) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(vii) यह कि आयात और निर्यात समुद्री बंदरगाह-बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दहेज, धरमतर, हल्दिया (कोलकाता बंदरगाह का हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स), काकीनाडा, कांडला, कोलकाता, कृष्णापटनम, मागडाल्ला, मंगलौर, मारमगोवा, मुलद्वारका, मुम्बई, मुन्धरा, नागापट्टिनम, न्हावा शेवा, ओखा, पारादीप, पिपाव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम तथा वदिनार के माध्यम से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बतूर, डाबोलिम(गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी स्थित किसी विमानपत्तन के जरिए अथवा आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी (आंध्र प्रदेश), बाबरपुर, बंगलौर, भदोही, भटिन्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, छेहाड़ता (अमृतसर), कोयम्बतूर, दादरी, डाम्पर (डेरा बस्सी), दौलताबाद (वंजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा), दिल्ली, डिगही (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गरही हरसारू, गौहाटी, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मलापुर, मंडीदीप (जिला रायसेन), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे), पीतम्पुर (इंदौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रुद्रपुर (नैनीताल), सलेम, सिंगनालूर, सूरत, सूरजपुर, तिरुपुर, तूतीकोरिन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वालुज (औरंगाबाद) स्थित किसी इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा अगरतल्ला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी रोड, चांगराबांधा, डावकी, घोजाडंगा, हिल्ली, जोगबानी, महादीपुर, नेपालगंज रोड, नौतनवा (सौनोली), पेटरापोल, राणाघाट, रक्सौल, सिंघाबाद तथा सुतारखंडी भू-सीमा शुल्क स्टेशन के जरिए अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं।

यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू-सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(viii) यह कि उक्त प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात जिम्मेदारी (मूल्य एवं मात्रा दोनों दृष्टि से) को उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट भारत में विनिर्मित अंतिम माल की आपूर्ति कर उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर पूरी की जाती है।

(ix) कि आयातकर्ता निर्यात संबंधी दायित्वों के निर्वहन का साक्ष्य उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उसकी संतुष्टि के लिये, दायित्वों को पूरा करने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के साठ दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जैसी भी स्थिति हो, अनुमति प्रदान करें, प्रस्तुत करता है;

(x) यह कि उक्त प्राधिकार को अंतरित नहीं किया जाएगा और उक्त सामग्रियों को अंतरित अथवा बेचा नहीं जायेगा ।

प्रावधान किया गया कि उक्त सामग्रियों को जॉब वर्क के लिए सामग्रियों के अंतरण की अनुमति प्रदान करने वाली संबद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने पर प्रसंस्करण के लिए जॉब वर्कर को अंतरित किया जा सकता है।

आगे शर्त यह है कि कार्य (जाब वर्क) के लिए ऐसा अंतरण उन इकाईयों के लिए नहीं किया जाएगा जो अधिसूचना संख्या 49/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 50/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों की तारीख 10.6.03, 32/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 1999, 33/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 1999, 8/04-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 जनवरी, 2004, 20/07-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 अप्रैल, 2007, 56/02- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 57/2-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 71/3-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 सितम्बर, 2003, 56/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 जून, 2003 तथा 39/01-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 जुलाई, 2001 की दृष्टि से उत्पाद शुल्क लगाये जाने से क्षेत्र आधारित छूट के लिए पात्र हैं ।

(xi) यह कि अंतिम माल जो उत्पादन करने वाले कारखाने से हटाए जाने पर उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त हैं, के लिए अपेक्षित संघटक और पूर्यों को इस शर्त के अधीन कि ऐसे संघटकों और पूर्यों के विवरण और मात्रा तथा साईट का पता उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट किए गए हों, इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और सीमाओं, यदि कोई हो, के अनुसार आयात के पोर्ट से परियोजना स्थल तक सीधे लाया जा सकता है।

2. शर्त यह है कि इस अधिसूचना के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के उपखंड (क), (ख), (ग), (i) और (ii) के अंतर्गत शामिल पैरा-1 में विनिर्दिष्ट अंतिम माल के लिए आवश्यक सामग्रियों के संदर्भ में रक्षोपाय शुल्क एवं प्रतिपाटन शुल्क के संदर्भ में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी,-

3. अंतिम माल के विनिर्माण के लिए आवश्यक कथित सामग्री का जब भारत में आयात किया जाएगा और निर्यातोन्मुखी इकाई, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रयोगिकी पार्क एवं साफ्टवेयर प्रयोगिकी पार्क को आपूर्ति की जाती है, तो उसे पैराग्राफ-1 में उल्लिखित शर्तों के अधीन कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत लगाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से उस

पर लगाने वाले रक्षोपाय शुल्क एवं प्रतिपाटन शुल्क से कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8 एवं 9क के अंतर्गत छूट दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

- (i) 'शुल्केय माल' से अभिप्राय उस माल से है जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है और जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है और जिस पर शून्य दर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता, और
- (ii) "इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" "निर्यातान्मुखी यूनिट" "सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" के वही अर्थ होंगे जो विदेश व्यापार नीति के कमशः पैरा 9.23, 9.24 और 9.60 में दिए गए हैं;
- (iii) "अंतिम माल" का अर्थ है -
  - (क) अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार/ शुल्क छूट/माफी स्कीम के अंतर्गत शुल्क मुक्त आपूर्ति प्रमाणपत्र के अंतर्गत आपूर्तियां;
  - (ख) निर्यातान्मुखी यूनिटों अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को दी गई आपूर्तियां;
  - (ग) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 के अंतर्गत लाइसेंसधारियों को माल की आपूर्ति;
  - (घ) उन एजेंसियों अथवा कोषों जिनके करार में सीमा शुल्कों को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन का प्रावधान है, की प्रक्रियाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अंतर्गत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों अथवा कोषों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को दी गई आपूर्तियां;
  - (ङ) उन एजेंसियों अथवा कोषों, जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं और विदेश में उत्पादित माल के लिए प्रदत्त शुल्क का भुगतान की गई कीमतों के आधार पर मूल्यांकन किया गया हो, की प्रक्रियाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अंतर्गत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा द्विपक्षीय एजेंसियों अथवा कोषों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपस्कर की आपूर्ति एवं उन्हें संस्थापित करना (महत्वपूर्ण ठेकों की एकल जिम्मेदारी);
  - (च) संयंत्र मशीनरी, उपकरणों, यंत्रों, रंगों और वाणिज्यिक उत्पादन के चरण तक संस्थापन उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ऐसे अन्य माल सहित संघटित अथवा असंघटित अथवा विघटित स्थिति में कारखानागत माल एवं उर्वरक संयंत्रों के लिए ऐसे कारखानागत माल के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के दस प्रतिशत तक पूर्जों की आपूर्ति जहां ऐसी आपूर्तियां सीमा शुल्क को शामिल किए बिना अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया का अनुसरण करके की जाती हैं;

- (छ) किसी भी परियोजना अथवा उद्देश्य जिनके संबंध में भारत सरकार का वित्त मंत्रालय अधिसूचना द्वारा शून्य सीमा शुल्क के साथ ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है और जहां आपूर्तियां सीमा शुल्क को शामिल किए बिना अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया का अनुसरण करके की जाती हैं, के लिए माल की आपूर्तियां;
- (ज) उपखंड (छ) में शामिल नहीं होने वाली ऊर्जा और रिफाईनरी परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति जहां आपूर्तियां सीमा शुल्क को शामिल किए बिना अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया का अनुसरण करके की जाती हैं ।
- (झ) निर्यातान्मुखी यूनिटों जैसे, घरेलू फ्रेट कंटेनर उत्पादकों द्वारा मैरिन फ्रेट कंटेनरों की आपूर्ति जहां ऐसे कंटेनर भारत से बाहर छः महीने की अवधि अथवा सीमा शुल्क उपयुक्त अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर निर्यात किए जाते हैं;
- (ञ) संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए की गई आपूर्तियां;
- (ट) न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए की गई माल की आपूर्तियां जहां ऐसी आपूर्तियां प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया का अनुसरण करके की जाती हैं ।
- (iv) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति 2009-2014 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 1/2009-2014, दिनांक 27 अगस्त, 2009 समय-समय पर यथा संशोधित के द्वारा किया है;
- (v) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी या क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22 से है) या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हो;
- (vi) "सामग्री" से अभिप्राय निम्न से है -
- (क) कच्चे माल, घटक, सहायक, उपभोग योग्य, उत्प्रेरक या उसके भाग से है जो परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी होते हैं;
- (ख) मेन्डेटरी स्पेयर्स जो लाइसेंस मूल्य के 10% तक सीमित है और परिणामी उत्पादों के साथ-साथ जिसका आयात जरूरी है;
- (ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी ईंधन;
- (घ) पैकेजिंग सामग्री जो कि परिणामी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए जरूरी है;
- (vii) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" के वही अर्थ हैं जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.49.1 में दिए गए हैं; और

(viii) "विशिष्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट " से अभिप्राय ऐसे सांविधिक लेखा-परीक्षक या चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत अथवा राज्य सरकार के बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर विधि के अंतर्गत आयातकर्ता के वित्तीय दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करता है।

[फा. सं. 605/58/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2009

**No. 112/2009-CUSTOMS**

**G.S.R. 710(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials required for the manufacture of the final goods when imported into India, from whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon respectively under sections 3, 8B and 9A of the said Customs Tariff Act, except to the extent specified in para 2 to this notification, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the importer has been granted Advance Authorisation for deemed export by the Regional Authority in terms of Paragraph 4.1.3(iii) of the Foreign Trade Policy permitting import of the said materials (hereinafter referred to as the said authorisation);

(ii) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(iii) that the said authorisation contains endorsements specifying, inter alia,-

(a) the description, quantity and value of materials allowed to be imported under the said authorisation; and

(b) the description and quantity of final goods to be manufactured out of, or with, the imported materials;

(iv) that in respect of imports made before the discharge of export obligation, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security, in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen percent per annum from the date of clearance of the said materials;

(v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation, if facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or the CENVAT Credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of

Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise officer or from a specified chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided further that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing CENVAT Credit under the CENVAT Credit Rules, 2004;

(vi) that in respect of imports made after the discharge of export obligation, and if facility under rule 18 or sub-rule 2 of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or the CENVAT credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (v);

(vii) that the imports and exports are undertaken through seaports at Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar, Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port) Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Magdalla, Mangalore, Marmagao, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadinar or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at Agra, Ahmedabad, Anaparthi (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi), Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Tirupur, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, , Waluj (Aurangabad) or through the Land Customs Station at Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may within the jurisdiction, by special order, or by a public notice, and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export from any other seaport/airport/inland container depot or through any land customs station;



(viii) that the export obligation as specified in the said authorization (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorization or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by supplying final goods manufactured in India which are specified in the said authorization;

(ix) that the importer produces evidence of having discharged obligation to supply final goods to the satisfaction of the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days from the expiry of the period allowed for fulfilment of obligation or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(x) that the said authorisation shall not be transferred and the said materials shall not be transferred or sold :

Provided that the said materials may be transferred to a job worker for processing subject to complying with the conditions specified in the relevant Central Excise notifications permitting transfer of materials for job work:

Provided further that no such transfer for purposes of job work shall be effected to the units located in areas eligible for area based exemptions from the levy of excise duty in terms of notification Nos. 49/03-CE and 50/03-CE both dated 10<sup>th</sup> June, 2003, 32/99-CE dated 8<sup>th</sup> July, 1999, 33/99-CE dated 8<sup>th</sup> July, 1999, 8/04-CE dated 21<sup>st</sup> January, 2004, 20/07-CE dated 25<sup>th</sup> April, 2007, 56/02-CE dated 14<sup>th</sup> November, 2002, 57/02-CE dated 14<sup>th</sup> November, 2002, 71/03-CE dated 9<sup>th</sup> September, 2003, 56/03-CE dated 25<sup>th</sup> June, 2003 and 39/01-CE dated 31<sup>st</sup> July, 2001;

(xi) that components and parts, required for manufacture of final goods which are wholly exempted from payment of excise duty when removed from the factory of production, may be taken directly from the port of import to the project site as per the procedures and limitations, if any, laid down by the Board in this regard subject to the condition that description and quantity of such components and parts and the address of the site have been specified in the said authorization.

2. The exemption from safeguard duty and anti-dumping duty shall not be available in respect of materials required for final goods specified in paragraph 1 which are covered under sub-clauses (a), (b), (c), (i) and (j) of clause (iii) of the explanation to this notification.

3. The materials required for the manufacture of the final goods, when imported into India and supplied to Export Oriented Unit, Electronic Hardware Technology Park and Software Technology Park, shall be exempted from the whole of the duty of customs leviable thereon, under the First Schedule to the said Customs Tariff Act and from the whole of additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively, under sections 3, 8B and 9A of the said Customs Tariff Act subject to the conditions mentioned in Paragraph 1.

Explanation, – For the purposes of this notification, -

(i) "Dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;

3530 42109-2

(ii) "Electronic Hardware Technology Parks", "Export Oriented Units" and "Software Technology Parks" have the same meaning as assigned to them in paragraph 9.23, 9.24 and 9.60 of the Foreign Trade Policy respectively;

(iii) "Final goods" means –

- (a) supply of goods against the Advance Authorisation scheme or the Advance Authorisation for Annual Requirement or the Duty Free Import Authorisation Scheme or the Duty Free Replenishment Certificate under the Duty Exemption/Remission Scheme;
- (b) supply of goods made to Export Oriented Units or Software Technology Parks or Electronic Hardware Technology Parks ;
- (c) supply of goods to the holders of licence under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy;
- (d) supply of goods made to projects financed by multilateral or bilateral Agencies or funds as notified by the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) under the International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those Agencies or funds where the agreement provides for tender evaluation without including the duties of customs;
- (e) supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies or funds as notified by the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) under international competitive bidding in accordance with the procedures of those agencies or funds, where the bids have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for the goods manufactured abroad;
- (f) supply of capital goods either in assembled or unassembled or disassembled condition including plant, machinery, accessories, tools, dies and such other goods used for installation purposes till the stage of commercial production and spares to the extent of ten per cent. of the Free on Rail value of such capital goods for fertilizer plants where such supplies are made after following the procedure of International Competitive Bidding without including the duties of customs;
- (g) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Government of India in the Ministry of Finance, by notification, permits the import of such goods at Zero duty of customs and where such supplies are made after following the procedure of International Competitive Bidding without including the duties of customs;
- (h) supply of goods to power and refinery projects not covered under sub-clause (g) where such supplies are made after following the procedure of International Competitive Bidding without including the duties of customs;
- (i) supply of Marine Freight Containers by Export Oriented Units namely, Domestic freight containers manufacturers where such containers are exported out of India within a period of six months or such further period as may be permitted by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;

- (j) supply of goods made to projects funded by United Nation Agencies;
- (k) supply of goods to nuclear power projects where such supply is made after following the procedure of Competitive Bidding;
- (iv) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No.1 /2009-2014, dated the 27th August 2009 as amended from time to time;
- (v) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant a licence under the said Act;
- (vi) "Materials" means –
  - (a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of final goods;
  - (b) mandatory spares within a value limit of ten per cent. of the value of the licence which are required to be exported along with the final goods;
  - (c) fuel required for manufacture of final goods;
  - (d) packaging materials required for packing of final goods;
- (vii) "Regional Authority" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.49.1 of the Foreign Trade Policy; and
- (viii) "Specified Chartered Accountant" means a statutory auditor or a Chartered Accountant who certifies the importer's financial records under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Sales Tax or the Value Added Tax laws of the State Government.

[F. No. 605/58/2009-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.